



साप्ताहिक

स्वदेशी इन्फ्रेडिबल

Web: www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 02

अंक : 11 गोरखपुर

रविवार 1

सितम्बर 2024

पृष्ठ : 8

मूल्य 02 रुपया

सुप्रीमकोर्ट के 75 साल पूरे

सीजेआई ने जिला न्यायपालिका को रीढ़ के रूप में वर्णित किया : पीएम

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार से शुरू होने वाले जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया है। जिला न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका पर कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया। उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष संविधान, संवैधानिक मूल्यों और अधिक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में उभरते भारत की यात्रा हैं। उच्चतम न्यायालय ने आपातकाल के काले दिनों में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर

राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखा। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष... ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है — भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है — एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष... मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के मार्ग दर्शन में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अदालत

के 800 से ज्यादा सदस्य भाग ले रहे हैं। चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका को न्यायपालिका की रीढ़ बताया और कहा कि यह कानून का अहम घटक है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय की तलाश कर रहा कोई नागरिक सबसे पहले जिला न्यायपालिका से संपर्क करता है। जिला न्यायपालिका कानून का अहम घटक है। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता और वे स्थितियां जिनमें न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्रदान करती है, यह निर्धारित करती है कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है या नहीं। सीजेआई ने कहा कि इसलिए जिला न्यायपालिका से बड़ी जिम्मेदारी



निभाने का आह्वान किया जाता है और इसे न्यायपालिका की रीढ़ के रूप में

वर्णित किया गया है। रीढ़ तंत्रिका तंत्र का अहम अंग है।

फैसले लोगों के खिलाफ नहीं होंगे, न्यायपालिका को यह विश्वास पैदा करना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय देने के लिए ट्रायल कोर्ट, जिला अदालतों और सत्र अदालतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा कि इन अदालतों को अधीनस्थ के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। वे अधीनस्थ नहीं हैं क्योंकि वे न्याय प्रदान करते हैं। सिब्बल ने कहा, उस स्तर पर न्यायपालिका को यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे और वे न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अपने लंबे कानूनी करियर पर विचार करते हुए, सिब्बल ने जिला अदालत स्तर पर जमानत दिए जाने की दुर्लभता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने

कहा कि अपने करियर में मैंने शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत दी हुई देखी हो। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि सीजेआई ने भी ऐसा कहा है क्योंकि उच्च न्यायालयों पर बोझ है। आखिरकार, निचली अदालत में जमानत एक अपवाद है।

सिब्बल ने कहा कि स्वतंत्रता एक संपन्न लोकतंत्र का मूलभूत आधार है और इसका गला घोटने का कोई भी प्रयास हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त और 1 सितंबर से शुरू होने वाले जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक टिकट और



सिक्के का अनावरण किया। अपने भाषण में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जिला अदालतों को अधीनस्थ के रूप में संदर्भित करने की औपनिवेशिक युग की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया।

कानूनी प्रणाली की रीढ़ को बनाए रखने के लिए, हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद करना चाहिए। आजादी के पचहत्तर साल बाद, हमारे लिए ब्रिटिश युग के एक और अवशेष — अधीनता की औपनिवेशिक मानसिकता को दफनाने का समय आ गया है।

आईएस धर्मद्र होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव, केंद्र ने जारी किया आदेश, नरेश कुमार की लेंगे जगह

नई दिल्ली। 1989 बैच के आईएसएस अधिकारी धर्मद्र को 1 सितंबर से दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने नरेश कुमार का स्थान लिया, जिनका विस्तारित कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले, धर्मद्र ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। गृह मंत्रालय ने धर्मद्र को दिल्ली प्रशासन में शीर्ष पद सौंपते

हुए स्थानांतरण की पुष्टि की। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर धर्मद्र के अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि धर्मद्र 1 सितंबर से या कार्यभार संभालने पर, जो भी बाद में आए, कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, 1987 बैच के आईएसएस अधिकारी नरेश कुमार का आम आदमी पार्टी (आप)

सरकार के साथ विवादास्पद संबंध रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दो बार दिया गया उनका सेवा विस्तार अगस्त के अंत में समाप्त होगा। पिछले साल, आप सरकार ने कुमार पर भूमि अधिग्रहण मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप हितधारकों को 897 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

पीएम मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, बोले- रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन मार्गों पर तीन वंदे भारत ट्रेनों

मोदी ने कहा कि इसी तरह कर्नाटक के लिए भी इस बार 7 हजार करोड़ से



को हरी झंडी दिखाई। ये तीन वंदे भारत ट्रेन मेरठ-लखनऊ, मदुरै-बंगलुरु और चेन्नई-नागरकोइल के बीच चलेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक, देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरै-बंगलुरु, चेन्नई-नागरकोविल और मेरठ-लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार... हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा है, अपार संसाधन और अवसर हैं। इसलिए, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है।

ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि आज लॉन्च की गई तीन वंदे भारत ट्रेनें देश के महत्वपूर्ण शहरों और ऐतिहासिक स्थानों को जोड़ने वाली हैं। टेम्पल सिटी मदुरै अब सीधे आईटी सिटी बंगलुरु से जुड़ जाएगा। इससे तीर्थयात्रियों और कर्मचारियों दोनों को लाभ होता है। इसी तरह, चेन्नई से नागरकोइल वंदे भारत कनेक्टिविटी से छात्रों, किसानों और कामकाजी पेशेवरों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि आज मेरठ-लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों को भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज यह क्षेत्र विकास के नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई-स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देशभर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालन हो रही हैं।

जन्माष्टमी उत्सव : सीएम योगी बोले- मेरा हर कर्म देश के नाम होगा, 2047 तक भारत बन जाएगा विकसित देश

(संवाददाता)
लखनऊ। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सहित शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इसके पहले मुख्यमंत्री दिन में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर मथुरा से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अपने भाषण में सीएम योगी ने कहा कि यह एकलौता

यूपी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की कराई जाएगी ग्रेडिंग

(संवाददाता)
लखनऊ। यूपी के मेडिकल कॉलेजों की ग्रेडिंग कराई जाएगी। ग्रेडिंग कराने का मकसद मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाना है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज की ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह ग्रेडिंग वहां मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं और पढ़ाई एवं शोध पर आधारित होगी। यह जानकारी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। केजीएमयू, एसजीपीजीआई और लोहिया संस्थान के साथ ही सभी राजकीय और स्वशासी मेडिकल कॉलेज में नई नई मशीनें लगाई जा रही हैं। सरकार विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। उन् वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 17 मेडिकल कॉलेज थे। अब 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। यहां की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से ग्रेडिंग कराई जा रही है।

ऐसा त्योहार है जो घर, मंदिरों के साथ जेल और थानों में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा किउत्तर प्रदेश पुलिस बल ने हानि-लाभ की चिंता के बिना कर्म को प्रधान माना। जिस पुलिस व प्रदेश को सबसे फिसड्डी मान लिया गया था। आज वह देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। कानून व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। अब प्रदेश में हर ओर सुख, शांति व सद्भावना है। प्रदेश के सभी 1585 थानों, 75 पुलिस लाइंस, 90 से अधिक जेलों में भव्यता से यह आयोजन हो रहा है, लेकिन 10 साल पहले यह संभव नहीं था। सरकारें डरती थीं कि आयोजन करेंगे तो क्या लाभ होगा। सीएम ने कहा कि श्रीमद्भगवतगीता में भगवान श्रीकृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन... हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता न करो। उन्होंने कहा कि हम अक्सर कर्म से पहले लाभ-हानि की चिंता करते हैं। ऐसा करने से हम उसके पुण्य से वंचित हो जाते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो पाप से कोई मुक्त नहीं कर सकता। लोककल्याण का कार्य किया है तो उसके पुण्य से कोई ताकत वंचित नहीं कर सकती। कर्म की प्रेरणा महत्वपूर्ण है।

श्रीकृष्ण ने धराधाम पर 125 वर्ष 8 महीने व्यतीत करने के बाद अपनी लीला को दिया विश्राम
सीएम योगी ने कहाकि भगवान श्रीकृष्ण श्री हरि विष्णु के पूर्व अवतार के रूप में मान्य हैं। यह वर्ष भारत के शास्त्रों की मान्यता के अनुसार लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव का है। उनकी लीलाओं का क्रम जन्म से ही प्रारंभ हुआ। इस धराधाम पर 125 वर्ष 8 महीने व्यतीत करने के बाद अपनी लीला को उन्होंने विश्राम दिया। अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लंबे समय तक उनकी लीलाओं को हम लोग प्रमाण के रूप में प्रयोग करते हैं।

श्रीमद्भगवतगीता की घर-घर में होती है पूजा
सीएम योगी ने कहा कि श्रीमद्भगवतगीता दुनिया का एकमात्र ऐसा पावन ग्रंथ है, जिसका अमर ज्ञान उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया। घर-घर में ग्रंथ के रूप में श्रीमद्भगवतगीता की हम लोग पूजा करते हैं तो भारत की न्यायपालिका भी उस ग्रंथ के प्रति उतनी ही श्रद्धा का भाव रखती है, जितना सनातन धर्मावलंबी रखता है। श्रीमद्भगवतगीता को मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है।

जीवन में चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थ
सीएम योगी ने कहा कि मनुष्य के जीवन में चार महत्वपूर्ण पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) हैं। आधारशिला धर्म से प्रारंभ होती है। वह कर्मों के माध्यम से अर्थ का उपार्जन करता है। जब कामनाओं की सिद्धि में उसका उपभोग करता है तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सामान्य मान्यता है, लेकिन श्रीमद्भगवतगीता के महत्वपूर्ण उपदेश आज भी हर भारतवासी को नई प्रेरणा प्रदान करते हैं।

2047 तक भारत को बनाएंगे विकसित
सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह में पीएम ने कहा था कि हमें अगले 25 वर्ष की कार्ययोजना के मुताबिक कार्य करना है यानी 2047 की जो पीढ़ी होगी, उसे हम विकसित भारत देंगे। जहां हर चेहरे पर खुशहाली होगी। कहीं दुख, दरिद्रता, अराजकता, गुंडागर्दी नहीं होगी। हर हाथ को काम और हर खेत को पानी होगा। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी ने पंच प्रण की बात कही। पंचप्रण में सबसे महत्वपूर्ण प्रण नागरिक कर्तव्य है।

जीवन में सफलता के लिए समाधान का मार्ग अपनाइए
सीएम योगी ने कहा कि हर नागरिक के अपने कर्तव्य भी होंगे। हर कोई अधिकार

की बात करता है,लेकिन कर्तव्यों की चर्चा

मेरा हर कर्म देश के नाम होगा



नहीं करता। जीवन में सफलता के लिए समाधान का मार्ग अपनाइए। जब लक्ष्य समाधान होगा तो सफलता प्राप्त होगी। जब समस्या पर चिंतन करेंगे तो दस बहाने मिल जाएंगे। टालमटोल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

समाधान के लिए बहाना नहीं, बल्कि परिश्रम, कर्म और पुरुषार्थ चाहिए। श्रीमद्भगवतगीता जैसा ग्रंथ कर्म की प्रेरणा देता है। प्रभु ने कुरुक्षेत्र में आमने-सामने खड़ी लाखों सेनाओं के बीच यही संदेश दिया। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जिसने धर्म व कर्म की प्रेरणा दी। उसका उपदेश रणभूमि में दिया गया है। यह उपदेश कर्म का है। कर्म के बिना धर्म, अर्थ व कामनाओं का साधन पूर्ण नहीं हो सकता है। न ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भारतीय मनीषा ने हमेशा कर्म को प्रधानता दी है।

सीएम ने कहा कि हमारे मन में विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। विरासत का सम्मान करते हुए विकास को बढ़ाएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि हर कोई अपने क्षेत्र में नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा हर कर्म देश के नाम होगा। देश के लिए सब कुछ समर्पित करूंगा, इस भाव के साथ कार्य करेंगे तो प्रभु की कृपा बनी रहेगी।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉ.दिनेश शर्मा, संजय सेठ, महापौर सुष्मा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, मुख्य सचिव मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव (गृह) दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे।

कर्बला के शहीदों के चालीसवें पर गमजदा माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस, शहीदों को दिया पुरसा

(संवाददाता)
लखनऊ। पुराने लखनऊ में कर्बला के शहीदों के चालीसवें पर चेहल्लुम का जुलूस निकला। अजादार नंगे पावं शहीदों को पुरसा देने के लिये जुलूस में साथ हो लिये। रोते हैं सब खास-ओ-आम चेहल्लुम हुआ तमाम, चले आओ ए जव्वालों चले आओ, मेरी आवाज पे लब्बैक पुकारे जाओ। दर्द भरे नौहों और या हुसैन, या हुसैन की सदाओं के साथ अजादारों के गमजदा चेहरे नम आंखों से कर्बला के शहीदों को पुरसा दे रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सहित कर्बला के 72 शहीदों के चालीसवें पर सोमवार को चेहल्लुम का जुलूस निकला। अजादार नंगे पावं शहीदों को पुरसा देने के लिये जुलूस में साथ हो लिये। जुलूस में शामिल मातमी अंजुमने अपने अलम के साथ आंखों में अश्क भरे मातम करती हुई चल रहीं थीं। कर्बला के शहीदों के चेहल्लुम के जुलूस में शामिल

होने के लिये अंजुमनं व अजादार बड़ी तादात में सुबह से ही विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित इमामबाड़ा नाजिम साहब पहुंचना शुरू हो गये। दोपहर में इमामबाड़े में मौलाना कल्बे जवाद नकवी के बेटे मौलाना कल्बे अहमद ने मजलिस को खिताब करते हुये कैदखाना ए शाम में मनाए गये चेहल्लुम का मंजर बयान किया तो वहां मौजूद अजादार गमगीन हो गये। मजलिस के बाद एक एक कर मातमी अंजुमन के निकलने कासिलसिला शुरू हुआ। जुलूस में सबसे आगे हजरत अब्बास का परचम था। इसके साए में शहर की तमाम अंजुमनं नौहाख्खानी करती हुई जुलूस में बढ़ चलीं। अंजुमनों के मातमदार जंजीर, कमा व सीनाजनी कर कर्बला के शहीदों को अपने खून से पुरसा दे रहे थे। इसके पीछे कर्बला के शहीदों के शबीह ए ताबूत और ऊंटो पर अमारियां शामिल थीं। इसके अलावा जुलूस में हजरत अब्बास की निशानी

अलम, हजरत इमाम हुसैन के छ माह के बेटे हजरत अली असगर का गहवारा और हजरत इमाम हुसैन की सवारी का प्रतीक जुलजनाह भी साथ-साथ था। इस बार एक क्विंटल ड्राई फ्रूट से बना आलम भी शामिल किया गया। अजादारों ने इन तबर्कुकात की जियारत कर दुआयें मांगी। जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट से नक्खास चौराहा,दूरियागंज, हैदरगंज, बुलाकी अड्डा, एवरेडी चौराहा होते हुये देर शाम तालकटोरा कर्बला पहुंच कर संपन्न हुआ। शहर में जन्माष्टमी और चेहल्लुम एक साथ होने की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। कर्बला के शहीदों के चालीसवें पर रविवार को ईराक की तर्ज पर राजधानी में भी अजादारों ने अरबईन वाक में शामिल होकर शहीदों का गम मनाया। राजधानी के बीकेटी स्थित कर्बला ए अब्बासिया व हजरतगंज स्थित इमामबाड़ा शाहनजफ से



अरबईन वाक निकाली गई। कर्बला तालकटोरा के लिये निकले अरबईन वाक में बड़ी तादात में काले लिबास में अजादार शामिल हुये।

दरअसल ईराक के कर्बला में हर साल चेहल्लुम के दिन अरबईन वाक का आयोजन होता है। इसमें दुनियां भर से लाखों अकीदतमंद शामिल

होते हैं। अकीदतमंद नजफ से कर्बला तक करीब 80 किमी का रास्ता पैदल तय कर कर्बला पहुंचते हैं।

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची

जम्मू । जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया है। पार्टी ने चरणवार उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इससे पहले भाजपा ने सोमवार को ही अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी थी। चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। सूची में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुख है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी और जनरल



(सेवानिवृत्त) वी के सिंह के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अन्य प्रमुख चेहरे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। बता दें कि राज्य में तीन चरणों में 18, 25 सितंबर और एक अक्तूबर को मतदान होंगे और चार अक्तूबर को परिणाम आएंगे।

‘असम को मिया की भूमि नहीं बनने दूंगा’, विधानसभा में क्यों बोले हिमंत बिस्वा सरमा

असम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि वह किसी का भी पक्ष लेंगे और मिया मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। सरमा नगांव में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्तावों पर विधानसभा में बोल रहे थे। प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यदि जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाए तो अपराध दर में वृद्धि नहीं हुई है। राज्य

विधानसभा में बोलते हुए, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि क्या आप (विपक्षी विधायक) पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं? निचले असम के लोग ऊपरी असम में क्यों जाएंगे? मैं असम को मिया की भूमि नहीं बनने दूंगा। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया, तो सरमा ने जवाब दिया, ‘पक्ष लूंगा। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं?’ उन्होंने जोर देकर कहा, ‘निचले असम के लोग ऊपरी असम में क्यों जाएंगे? ताकि मिया मुस्लिम असम

पर कब्जा कर सकें? हम ऐसा नहीं होने देंगे। गरमागरम बहस के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सदन के वेल में आ गए, जिसके कारण स्पीकर बिस्वजीत दैमारी को कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस, एआईयूडीएफ और सीपीआई (एम) के विधायकों और एकमात्र निर्दलीय विधायक अखिल गोर्गोई ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित राज्य में बढ़ते अपराधों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए चार स्थगन प्रस्ताव पेश किए थे।

ममता बनर्जी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट?

कोलकाता में बेकाबू हालात के बीच ये नई मांग कैसे आई सामने

कोलकाता । पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से

को बचाने का आरोप लगाया और मांग की कि सीबीआई उनका पॉलीग्राफ परीक्षण कराए। राज्य की राजधानी में

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी ने बनर्जी को तानाशाह बताया और उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के बल प्रयोग की भी निंदा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह चिंताजनक है। यह संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कोई डॉक्टर है, तो वह ममता बनर्जी हैं। भाटिया ने दावा किया कि पुलिस आयुक्त ने बलात्कार और हत्या को आत्महत्या बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए।



प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पत्थर फेंके जाने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता नजर आया। भीड़ को पीछे करने के लिए वॉटर केनन का प्रयोग किया गया। कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया। वहीं कुछ महिलाओं को चोटें भी आई। एक तस्वीर जिसमें टीशर्ट से पकड़कर छात्र को घसीटते हुए पुलिस द्वारा ले जाया गया। ममता बनर्जी इस्तीफा दें, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो इन मांगों के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज पर

दही हांडी के दौरान बड़ा हादसा, 41 लोग घायल; 8 की हालत गंभीर

महाराष्ट्र। मुंबई में श्रद्धा हांडी उत्सव के दौरान बहुमंजिला पिरामिड बनाने वाले कुल 41 श्रद्धा हांडी घायल हो गए हैं। ये सभी गोविंदा मटकी फोड़ने के लिए ऊपर चढ़े थे, इस दौरान ये तेजी से नीचे गिरे और घायल हो गए। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बताया कि घायल गोविंदाओं को इलाज के लिए नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों में ले जाया गया है। बीएमसी ने बताया कि 41 घायल गोविंदाओं में से आठ अस्पताल में भर्ती हैं, 26 का इलाज ओपीडी में चल रहा है और सात गोविंदाओं को आवश्यक इलाज के बाद अस्पताल से छुटी दे दी गई है। दही हांडी देखने के लिए मुंबई और ठाणे में कई स्थानों पर भीड़ उमड़ी। मुंबई के वर्ली, दादर, ठाणे के खोपट और टेम्पी नाका जैसे पारंपरिक स्थानों पर बड़ी भीड़ देखी जाती है और लटकी हुई हांडी को तोड़ने वाली विजेता गोविंदा टीम के लिए उच्च पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।

भारतीय वीजा केंद्र को पुलिस ने चारों ओर से घेरा, हाई कमीशन ने युनुस सरकार से की ये मांग

ढाका। एक सुविधा पर सैकड़ों लोगों के विरोध के बाद भारत ने बांग्लादेश में अपने वीजा केंद्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है, बांग्लादेश पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि



राजधानी शहर के राजनयिक क्षेत्र में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों ने सोमवार को ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर (आईवीएसी) पर विरोध प्रदर्शन किया। मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हालांकि कोई तोड़फोड़ या हिंसा नहीं हुई, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एक बड़ी पुलिस टुकड़ी को इलाके में भेजा गया। विरोध के बाद, भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को एक नोट वॉर्बल या एक अहस्ताक्षरित राजनयिक पत्राचार भेजा, जिसमें देश भर में भारतीय वीजा केंद्रों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रमुख मैनुल हसन ने मंगलवार को एचटी को बताया कि

भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर जमकर हंगामा किया। कतारों में इंतजार करने के बावजूद कई आवेदकों को वीजा नहीं मिलने पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वतारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मजहरुल इस्लाम ने न्यू एज को बताया कि प्रदर्शन सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक स्थिति पर काबू पा लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस के अनुसार, लोग अपने दस्तावेज लेने के लिए वीजा केंद्र के बाहर कतार में खड़े थे — एक लाइन जो लगभग एक किलोमीटर लंबी थी। हालांकि, जब केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वीजा की प्रक्रिया में देरी हो रही है, तो स्थानीय लोग नाराज हो गए और नारे लगाने लगे। समूह को यह कहते हुए सुना जा सकता है।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत, किरण चौधरी बनी निर्विरोध सांसद

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी की

उम्मीदवारी का समर्थन किया था।



नेता किरण चौधरी हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। वह इस चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। किरण चौधरी को हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव में मंगलवार दोपहर 3 बजे नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। हरियाणा की पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बुधवार को उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। प्रतियोगिता में अकेली उम्मीदवार होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को हरियाणा विधानसभा सचिवालय में उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर साकेत कुमार द्वारा शाम 4.33 बजे प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी भी मौजूद थे। इससे पहले जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था तो जेजेपी के चार बागी विधायकों ने भी उनकी

हरियाणा में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए उपचुनाव में किसी अन्य पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। यह सीट कांग्रेस के दीपेन्द्र सिंह हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। उनका राज्यसभा का कार्यकाल 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त होना था। इसी कड़ी में भाजपा ने किरण चौधरी (69) को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया कांग्रेस छोड़ने के करीब दो महीने बाद किरम चौधरी जून में अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हुई थीं। किरण चौधरी हरियाणा विधानसभा में तोशाम सीट का प्रतिनिधित्व करती थीं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है।

सम्पादकीय

सुरक्षा की पेंशन

आखिरकार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए इस उलझन को दूर करने का प्रयास किया है। उसने पुरानी पेंशन और एनपीएस के बीच का रास्ता निकाल जहां कर्मचारियों के हितों को तरजीह दी है, वहीं राजकोषीय दबाव को भी कम किया है। निस्संदेह, हाल में घोषित एकीकृत पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को संबल मिलेगा। जिसमें एक निश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन का आश्वासन तथा मुद्रास्फीति के दबाव से राहत का प्रयास सम्मिलित है। इस योजना में सेवानिवृत्ति से पहले वर्ष में बारह माह के औसत मूल वेतन का पचास फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। जिसमें कर्मचारी का योगदान तो दस फीसदी ही रहेगा, लेकिन सरकार का योगदान 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा। यह लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा, लेकिन दस साल की सेवा वाले व्यक्ति को भी दस हजार पेंशन का लाभ मिलेगा। निस्संदेह, इस निर्णय के राजनीतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में चुनाव कार्यक्रम घोषित है और साल के अंत तक महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव होने हैं। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को हवा देते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था। कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में आये जनादेश का एक बड़ा कारण पुरानी पेंशन का मुद्दा था। हालांकि, राजस्थान व पंजाब आदि राज्यों में यह मुद्दा वैसा प्रभावी नजर नहीं आया। निस्संदेह, मुद्दा लोकलुभावन तो था लेकिन पुरानी पेंशन को लागू करने से भारी वित्तीय दबाव बढ़ने की चिंता जतायी गई। तभी बीते साल आरबीआई ने ओपीएस के विकल्प का चयन करने वाले राज्यों पर बढ़ने वाले आर्थिक दबाव पर चिंता जतायी थी। निस्संदेह, इससे सरकारों का राजकोषीय घाटा निरंतर बढ़ने का भी खतरा था। जिसके चलते इस योजना को वर्ष 2004 में समाप्त किया गया था। फिर उसी राह पर लौटना व्यावहारिक भी नहीं था। दरअसल, राजग सरकार का कहना है कि एकीकृत पेंशन योजना वित्तीय अनुशासन के अनुरूप है, जो कि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ कर्मियों के अंशदान से मूर्त रूप लेती है। जिससे जहां एक ओर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी, वहीं राजकोषीय विवेक में भी संतुलन बन सकेगा। दरअसल, विपक्षी दलों द्वारा पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाने के बाद केंद्र सरकार ने इसके विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। फिर अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की प्रधानी में बनी कमेटी ने चिंतन-मनन के उपरांत जो सिफारिश सरकार को सौंपी, बीते शनिवार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने उसे हरी झंडी दिखा दी। बहरहाल, यह लोकतंत्र की खूबसूरती कही जा सकती है कि जन दबाव में सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। निस्संदेह, पूरा जीवन राजकीय सेवा में लगाने वाला कर्मचारी रिटायर होने के बाद आर्थिक असुरक्षा में धिर जाता है। वह भी तब जब देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नगण्य हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आय के साधन सीमित होने, बढ़ती उम्र की बीमारियों के दबाव तथा बच्चों की अनदेखी के चलते पूर्व कर्मियों को उपेक्षित जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है। यही वजह है कि देश में एकीकृत पेंशन योजना को सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। विपक्षी दल भी विरोध करने के बजाय कह रहे हैं कि उनकी मुहिम से ही यह पेंशन योजना अस्तित्व में आयी। यह सुखद ही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये कर्मचारी हित में सकारात्मक बदलाव संभव हुआ। आगामी वर्ष में एक अप्रैल को लागू होने वाले इस फैसले से केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद योजना का लाभ मिलेगा, और यदि राज्य योजना को लागू करते हैं तो इसका लाभ करीब नब्बे लाख कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के लिये एनपीएस के विकल्प भी खुले रहेंगे। दूसरी ओर सरकार को निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों की वित्तीय असुरक्षा को महसूस करते हुए उन्हें नई पेंशन का लाभ देने की दिशा में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बहरहाल, केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को एक राहत देने की कोशिश की है।

मोदी की यूक्रेन यात्रा में निहित संदेश

ज्योति मल्होत्रा

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव के एक बगीचे में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को श्रद्धा सुमन भेंट करने के अवसर पर कुछ अति उत्साही भारतीयों द्वारा 'हर-हर मोदी' और 'जय श्री राम' के नारे लगाने से माहौल की संजीदगी को कुछ हद तक ठेस पहुंची होगी। कुछ मिनट बाद, रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों के यादगार स्मारक के सामने मोदी और व्लादिमीर जेलेन्स्की के बीच हुई मुलाकात में भावनाएं जिस प्रकार स्पष्टतः उमड़ती दिखी, वह भारत के समक्ष उत्पन्न उस धर्मसंकट का भी द्योतक रही, जो इस युद्ध में मध्य मार्ग चुनने से बना है। पृष्ठभूमि समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और इसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए दृष्टि कर्षण की। भारतीयों के अलावा बहुत से रूसी भी इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन बारीकी से देखने पर, अन्य संदर्भ सामने आ जाते हैं। दो साल पहले, नाटो का विस्तार ठीक अपनी सीमा तक पहुंचते देख असुरक्षा की भावना से भरे रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। अब यह लड़ाई ऐतिहासिक रूप से साझेदार और सह-धर्मियों के मध्य हार-जीत को लेकर कम बल्कि विश्व पटल पर रूस की जगह को लेकर रूस-अमेरिका के बीच जारी खींचतान की वजह से ज्यादा है। हर कोई, विशेष रूप से यूक्रेनियन, जानता है कि अगर अमेरिका के साथ-साथ पश्चिमी जगत के बड़े हिस्से ने जेलेन्स्की के लोगों को अत्याधुनिक हथियार नहीं दिए होते, तो युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और निर्दोष लोगों की मौत लगातार जारी है। बड़ी शक्तियों का राजनीतिक खेल हावी हो चुका है। यूक्रेन का यह युद्ध अब इस उद्देश्य को लेकर है 'कौन बनेगा दुनिया का दादा'? 1991 के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद, साफ है अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति वाला अपना ओहदा छिन जाने को लेकर तैयार नहीं। रूसी भले ही आज अमेरिकियों जितने मजबूत न हों, लेकिन फिर भी काफी शक्तिशाली हैं, और उनका जोर इस बात पर है कि शीर्ष पर एक से अधिक के लिए गुंजाइश है। हमेशा की तरह, चीन 'देखो और इंतजार करो' वाली अपनी नीति के साथ, खुद को दोनों पक्षों के साथ खड़ा दिखाए रखने को उत्सुक और इच्छुक है दृष्टि जहां एक ओर वे अमेरिका के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं वहीं ठीक उसी वक्त व्लादिमीर पुतिन की घर और बाहर, दोनों जगह, प्रासंगिक बने रहने की चिंता भरी जरूरत का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत का रुख क्या है? जारी इस महा खेल में भारत किसकी तरफदारी करे, इसका उत्तर जटिल है। मोदी ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कीव में



जब जेलेन्स्की से कहा: 'भारत शांति की दिशा में किसी भी प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने' को तैयार है, इससे कुछ पल पहले, दोनों ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया था दृष्टि कुछ हद तक उस लंबी गलबही की तरह जो मोदी और पुतिन ने छह सप्ताह पहले मॉस्को के बाहरी हिस्से में स्थित पुतिन के घर में डाली थी और जिसको लेकर जेलेन्स्की ने खुले तौर पर माना था कि इसने उन्हें परेशान कर डाला था। कुछ क्षण बाद, मोदी ने अपना बायां हाथ जेलेन्स्की के बाएं कंधे पर रखा, जैसा कि बड़े भाई अक्सर अनुज के साथ करते हैं, और कुछ देर वहीं रखो रखा, इस बीच फोटोग्राफरों ने कई तस्वीरें लीं। ऐसा लगता है कि मोदी वास्तव में द्रवित हुए दृष्टि यह अच्छी बात है कि वे हुए। भारत आमतौर पर कमजोर के साथ खड़ा होता है दृष्टि पूर्व पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का सहयोग इसका एक बढ़िया उदाहरण है। लेकिन यहां तो कुछ और ही होता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो मोदी को एक तरह से राजी किया गया हो कि वे यूक्रेनियों के साथ खड़े दिखाई दें दृष्टि और इस तरह, परोक्ष रूप से अमेरिका के साथ। अमेरिकियों ने मोदी की मॉस्को यात्रा पर अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तथ्य यह है कि पिछले दो वर्षों में, भारत द्वारा रूस से रियायती दर पर भारी मात्रा में तेल खरीदने से व्यापार के आंकड़े में भारी उछाल बनने के बावजूद, भारत-अमेरिका के बीच लेन-देन अभी भी भारत-रूस व्यापार से दोगुना है।

पश्चिम में जो लोग यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से इनकार करने पर भारत की आलोचना करते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है दृष्टि स्वयं पर पक्षपाती होने का आरोप लगने के जोखिम पर, उदाहरणार्थ, उनसे पूछा जाए : 'आपने इस्त्राइल द्वारा गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र परिसर पर की जाने वाली बमबारी रोकने के लिए क्या किया?' या फिर, मुख्य सहयोगी पश्चिमी मुल्क दृष्टि जिनमें अधिकांश पांच सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं दृष्टि क्या इनमें किसी एक ने उस वक्त असहमति की एक छोटी अंगुली तक उठाई, जब 2003 में सद्दाम हुसैन द्वारा सामूहिक विनाश

के हथियारों का उपयोग करने की आशंका जताते हुए स्पष्ट रूप से झूठी अफवाह फैलाकर, अमेरिका ने इराक पर बमबारी करने का फैसला किया था। रुको जरा, एक सेकंड दृष्टि सद्दाम के पास ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इस बीच, ठीक उसी समय जब मोदी यूक्रेन में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वाशिंगटन डीसी की यात्रा क्या महज़ इत्तेफाक है—अमेरिकियों के साथ एक-दो रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करना एक अच्छी बात है। लेकिन यदि यह संयोग नहीं है, तो इससे दो अन्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। प्रथम, अमेरिका अपने फैसलों पर जताई असहमति को लेकर सहज नहीं है, भले वह किसी सहयोगी लोकतंत्र ने दिखाई हो। अवश्य ही मोदी को कीव में जेलेन्स्की से मिलने के लिए राजी करने की कोशिश में, दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के अलावा कई अन्य पश्चिमी राजधानियों के बीच काफी बातचीत हुई होगी। और दूसरा, स्पष्ट है कि यूक्रेन का मामला मोदी की अब तक की सबसे कठिन विदेश नीतिज्ञ चुनौती बनता जा रहा है। यहां, फिर से याद रखें कि यूक्रेन मुद्दे की अहमियत अमेरिकियों के लिए केवल एक बहानेभर की है। यूक्रेन के साथ खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है—पुतिन या बाइडेन जो कुछ भी कहें, अपनी और से चीजों की जांच करना बेहतर होगा। यदि प्रधानमंत्री मोदी 'बिलियों की लड़ाई' में पैतरेबाजी करने में सक्षम रहे, जैसा कि उनके कई पूर्ववर्तियों ने कर दिखाया, तो वे विश्व पटल पर भारत का विशिष्ट स्थान पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। निश्चित रूप से, दुनिया बदलाव के किसी भी स्व परिभाषित संकेत पर नजर रखेगी दृष्टि जैसा कि मोदी की मास्को यात्रा पर बनाए रखी।

पश्चिमी जगत भारत का साथ जीतना चाहता है दृष्टि अपनी धूल-मिट्टी के बावजूद, यह खांटी लोगों का देश है। इसके अतिरिक्त, बाइडेन, ऋषि सुनक, इमैनुएल मैक्रॉन, ओलाफ स्कॉल्ज और कुछ अन्य, जो सब एक ही पाले में हैं, इनके बरक्स भारत का रुख सदा अपना रहा है दृष्टि राष्ट्रीय हित और उच्च नैतिकता के बीच लंबी और कठिन डगर एक चुनौती है, वह जिसके प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए हाल-फिलहाल, प्रधानमंत्री द्वारा कीव से वापसी की रेलगाड़ी पकड़ने के साथ, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा अपने आप में संदेश है, भारत और दुनिया, दोनों के लिए।

खुद में सुधार से संवरेंगी बच्चों की

शिखर चंद जैन
दो दिन पहले ही मेघा लंबे समय
बाद पीहर आई थी। साथ में उसका 4

साल का बेटा अभिनव भी आया था।
मेघा की मम्मी ने देखा कि अभिनव को
जब तक हाथ में मोबाइल न दो तब

कीव यात्रा के मायने

कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा पूर्वी व पश्चिमी देशों के बीच कूटनीतिक संतुलन साधने की कवायद भर है। यह यात्रा भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण रहा। जो एक ओर रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों को बनाये रखना तथा दूसरी ओर पश्चिम के साथ बढ़ते जुड़ाव के बीच संवेदनशील संतुलन बनाने की कोशिश है। दरअसल, मोदी की यूक्रेन यात्रा कुछ समय पहले संपन्न मास्को यात्रा के बाद हुई। जो रूस-यूक्रेन संघर्ष की जटिल भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटने की भारत की संवेदनशील पहल को ही दर्शाती है। दशकों से रूस भारत का आजमाया दोस्त है। रूस से बेहतर संबंध हमारी विदेशी नीति की आधारशिला भी रही है। विशेष रूप से रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में, तमाम रक्षा उपकरण व कलपुर्जों को लेकर भारत रूस पर निर्भर रहा है। मोदी की रूस यात्रा ने जहां दोनों देशों के रिश्तों को नये आयाम दिए, वहीं पश्चिम को यह संदेश भी दिया कि रणनीतिक स्वायत्तता पर हम बाहरी दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं यूक्रेन के साथ सीधे जुड़ना विश्व बिरादरी को यह संदेश देने का प्रयास भी है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता को बनाये रखने का पक्षधर है। जो कि वैश्विक शांति व सुरक्षा के मौलिक तत्व भी हैं। वह बात अलग है कि मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन व पश्चिमी देशों की तल्लख प्रतिक्रिया सामने आई थी। मोदी की यूक्रेन यात्रा को उसी घटनाक्रम के आलोक में देखा जा सकता है। बहरहाल, कहा जा सकता है कि इस तरह भारत ने यूक्रेन से जुड़ाव के जरिये जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया है, वहीं मास्को यात्रा से रूस के साथ परंपरागत संबंधों को कुशलतापूर्वक बनाये रखने में सफलता हासिल की है। भारत ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा से पश्चिम की चिंताओं को भी दूर किया है। वैश्विक कूटनीति में यह संतुलन बनाना बेहद जटिल कार्य है। दरअसल, भारत पूर्व व पश्चिमी खेमे से खुद को अलग रखकर अपनी कूटनीति के आधारभूत तत्व गुटनिरपेक्षता की नीति को भी बनाये रखना चाहता है। भारत ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के जरिये यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भारत यूक्रेन के संघर्ष के प्रति उदासीन नहीं है। यह भी कि भारत शांति के लिये होने वाली बातचीत में शामिल होने का इच्छुक है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के साथ कई समझौतों में भागीदारी भारत के लिये ऊर्जा सुरक्षा और यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों के हेतु नये रास्ते खोल सकती है। वह भी ऐसे समय में जब पश्चिम रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा है। जिसमें भारत को कूटनीतिक व महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। बहरहाल, मोदी की मास्को व कीव की यात्राएं भारत की कूटनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करती हैं। जिसमें सावधानी से पूर्व-पश्चिम में संतुलन साधने का सार्थक प्रयास हुआ है। जो तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में अपने रणनीतिक हितों को साधने की सफल कोशिश भी है। वहीं बातचीत से शांति स्थापना के प्रयासों के लिये हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

साधो दुनिया एक बाज़ार, रिश्ता सिर्फ कारोबार

आलोक पुराणिक

पीएम मोदी यूक्रेन गये, इससे पहले वह यूक्रेन के दुश्मन रूस में गये। पीएम मोदी रूस से कच्चा तेल लेते हैं, डिस्काउंट पर। पीएम मोदी यूक्रेन के बास अमेरिका से सुरक्षा समझौते करते हैं। भारत का हाल दुनिया के बाजार में कबीर वाला है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सबसे खरीदेंगे और सबको बेचेंगे। साधो दुनिया एक बाज़ार, सारा रिश्ता कारोबारा। कारोबार ही परम सत्य है। बाकी सब फर्जी बातें हैं। इस दुनिया में दुकानदार किसी का नहीं, वह सिर्फ मुनाफे का है। ऐसे ही ग्राहक किसी का नहीं है, वह सबसे सस्ती कीमत का है। यही परम सत्य है। इस बात को रूस के प्रेसीडेंट पुतिन समझते हैं इसलिए बुरा न मानते। भारत उनका ग्राहक है, ग्राहक से नाराज न हुआ जाता। नाराजगी रिश्तेदारों में शोभा देती है। ग्राहक से कोई नाराज न होता। अगर भारत रूस का ग्राहक न होता, तो पुतिन साहब फौरन बता देते कि भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए था। ग्राहकों से तमीज से बात करनी होती है यह भी एक बाजारी सत्य है। अमेरिका भी समझता है कि भारत कई आइटमों का ग्राहक है उससे तमीज से बात की जाये। भारत अब वर्ल्ड मार्केट में बड़ा कस्टमर है, उसके विदेशी मुद्रा कोष में करीब 675 अरब डालर हैं। भारत का हाल विश्व बाजार में उस कस्टमर का—सा है जो हाल में अमीर हो गया है और अब खुलकर कहता है कि अभी पुराने टाइप का बर्ताव नहीं चलेगा, हमको फुल इज्जत मांगता। इज्जत अब बाजार में ही मिल रही है। दुनियाभर में शांति लाने का एक ही जरिया है कि सब कस्टमर बन जायें। फलस्तीनी अगर अमीर कस्टमर होते, तो सब उनकी चिंता करते। इस्राइल से दुनियाभर के देश कहते कि भाई बहुत हो गया। अब बंद करो। फलस्तीन की चिंता दुनिया का कोई बड़ा देश इसलिए नहीं कर रहा है कि किसी का भी धंधा मंदा नहीं हो रहा है, फलस्तीन की तबाही से। उधर हमारा के लिए आतंक एक कारोबार है। हमारा इस्राइल से जितना लड़ाई लड़ेगा उसे उतना ही ज्यादा फंड मिलेगा तमाम देशों से। हमारा के बड़े नेता अय्याशी कर रहे हैं, भर-भर के नोटों में डूबे हुए हैं।

तक वह खाना भी नहीं खाता। यूट्यूब पर कार्टून देखता रहता है और मेघा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। अभिनव की रुचि खेलने-कूदने या बाहर जाने में नहीं। यानी डिजिटल एडिक्शन।

इस्तेमाल से श्रवण शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है।
व्यवहार और संवाद पर असर
इस टेक एडिक्शन से घर-परिवार में आपसी संबंधों में भी सरसता व

सुलझाना, चेस या लूडो जैसे बोर्ड गेम्स खेलना, आउटडोर एक्टिविटीज और भागदौड़ वाले खेल खेलना आदि पर ध्यान दें।
चिंता विशेषज्ञों की



बस दिनभर मोबाइल में गाने सुनता है ,कार्टून देखता है या फिर गेम खेलता है। मम्मी ने मेघा से इस बात का जिक्र किया तो बोली, 'क्या करूं मम्मी मैं तो समझाकर, डांटकर थक गई। मानता ही नहीं।' मम्मी लगभग डांटते हुए बोली, 'मानेगा कैसे? तेरा भी तो यही हाल है! दिन भर रील्स देखती है, इंस्टाग्राम और फेसबुक में लगी रहती है। बच्चे तो अपने मां-बाप से या भाई-बहन से ही अच्छी-बुरी चीज़ सीखते हैं। पहले आप खुद तो सुधरें।' सही भी है, बच्चों को हम डिजिटल दुनिया से दूर रहना तभी सिखा सकेंगे जब हम सीखेंगे। बता दें कि डिजिटल एडिक्शन अपनी भावनाओं का खुद के नियंत्रण से बाहर होना है जिसमें व्यक्ति डिजिटल गैजेट्स, प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म का जुनून की हद तक इस्तेमाल करने लगता है। इसमें इंटरनेट, वीडियो गेम, मोबाइल व लैपटॉप और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का बेतहाशा उपयोग शामिल है।

डिजिटल एडिक्शन के दुष्प्रभाव
आज हर कोई मोबाइल ,टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज्यादा इस्तेमाल से परेशान है। इससे स्लीप साइकल बिगड़ रहा है। सरकेडियम रिदम भी प्रभावित हो रहा है। इससे हमारे शरीर में नकारात्मक मानसिक, व्यावहारिक और शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। लर्निंग पॉवर कम हो रही है। मोटापा, चिड़चिड़ापन, अवसाद, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं मानो हमारे ही खुले निमंत्रण पर हम पर कब्जा करती जा रही हैं। भारत की 30 फीसदी आबादी नौद न आने की समस्या से ग्रस्त हो चुकी है। इससे हमारी क्रियाशीलता और शारीरिक व मानसिक विकास पर भी खराब असर पड़ रहा है। ईयर पीस के ज्यादा

संवेदनशीलता कम हो रही है। अनियंत्रित स्क्रीन टाइम हमारे सामाजिकता व्यवहार और परस्पर संवाद पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक आज औसत रूप से हर व्यक्ति 6. 58 घंटे स्क्रीन पर बिता रहा है। टेक एडिक्शन के कारण हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं।

डिजिटल डिफिक्शन के उपाय
मोबाइल पर फिजूल कंटेंट से बच्चों को छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है। घर में आप घर में माहौल बदलें। खुद भी मोबाइल रील्स आदि से दूरी बनाएं, डिजिटल डिजिटल डिफिक्शन का पालन करें और बच्चों को भी सिखाएं। जानिये उपाय—

डिजिटल फ्री टाइम व स्थान
कोई ऐसा स्थान तय करें जहां आप रहेंगे तो सिर्फ कॉल रिसीव करेंगे, स्क्रीन स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। या फिर कोई समय तय करें जब आप फोन या टीवी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप इस टाइम सिर्फ बातें करेंगे, किताबें पढ़ेंगे या जरूरी काम करेंगे।

बनाएं स्क्रीन टाइम टेबल
घर में कुछ ऐसे नियम बनाएं कि हर कोई अपनी उम्र के मुताबिक स्मार्टफोन या गैजेट्स में इन्वॉल्व हो। बाकी समय सब अपने रूटीन काम करें। बच्चे खेलें-कूदें और पढ़ाई करें, बड़े आपस में पारिवारिक मुद्दे डिस्कस करें व अपनी व्यावसायिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं।

बच्चों को क्रिएटिव विकल्प भी दें
जब आप बच्चों को स्मार्टफोन से दूर करेंगी तो उन्हें एक खालीपन और बोरियत महसूस होगी। इसके लिए उन्हें कुछ एंटरटेनिंग, क्रिएटिव और ज्ञानवर्धक आइडिया दें। जैसे कविताएं या कहानी पढ़ना, प्रेरक प्रसंग या महापुरुषों की जीवनी पढ़ना, पहेलियां

बच्चों के डिजिटल बिहेवियर से जुड़ी जो बात व्यवहार विशेषज्ञों को परेशान कर रही है वह है 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में अत्यधिक वीडियो गेम्स खेलने की प्रवृत्ति, हिंसक या फिजूल रील्स देखने और उनकी नकल करके खुद रील बनाने की प्रवृत्ति और पोर्नोग्राफी देखने की लत। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पैरेंट्स को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। डांटने पर बात बिगड़ेगी। बेहतर होगा कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उनकी भावनाओं को जानें, बात सुनें और समझें। उनसे अपने अनुभव शेयर करें ताकि वे अकेलेपन से उबरने के लिए डिजिटल दुनिया का सहारा न लें।

इस टेक एडिक्शन से

घर-परिवार में आपसी संबंधों

में भी सरसता व

संवेदनशीलता कम हो रही

है। अनियंत्रित स्क्रीन टाइम

हमारे सामाजिकता व्यवहार

और परस्पर संवाद पर

प्रतिकूल असर डाल रहा है।

एक अध्ययन के मुताबिक

आज औसत रूप से हर व्यक्ति

6. 58 घंटे स्क्रीन पर बिता

रहा है। टेक एडिक्शन के

कारण हम लंबे समय तक

एक ही जगह बैठे रहते हैं।

राजनेताओं से मुक्त पुलिस ही दिलाएगी न्याय

बीएल वोहरा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल
कॉलेज एवं अस्पताल में एक युवा

मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान
लेते हुए तीखी टिप्पणियां की हैं। इसने
राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा है

अपराध और राजनीतिक कीचड़
उछालना कोई नई बात नहीं है। वर्षों
से यही होता आया है और होता रहेगा,

अपना काम कुशलतापूर्वक नहीं करने के लिए दोष पुलिस नेतृत्व पर भी आता है, दुर्भाग्यवश इसके पीछे काफी हद तक वजह है भ्रष्टाचार और करिअर हितों के कारण फर्ज से समझौता करना, लिहाजा कई पुलिसकर्मी राजनेताओं से हाथ मिला लेते हैं, मुख्यतः इसलिए भी क्योंकि यह राजनेता ही हैं, जो उन्हें तरक्की-इनाम दिलवा सकता है या फिर कई तरीकों से तंग कर सकता है। हम अभी भी 1861 के कानून पर अटके पड़े हैं। एक बार पुलिस को संविधान और संसद के प्रति जवाबदेह बना दिया जाए तो स्थिति में काफी सुधार होगा। तब हमारी पुलिस भी कई अन्य देशों की भांति बिना किसी डर के, कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगी। हालांकि, सोली सोराबजी समिति द्वारा मॉडल पुलिस अधिनियम बनाए कई साल गुजर गए। लेकिन कोई भी इस पर अमल नहीं करना चाहता, यहां तक कि केंद्र सरकार भी नहीं। हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद 2006 में पुलिस सुधारों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, वह भी अपने निर्देशों पर अक्षरशः कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य सरकारों को अवमानना नोटिस जारी करने को उत्सुक नहीं है। सूबा सरकारों ने उन निर्देशों पर महज लीपापोती की है। अंग्रेजों ने हमें पुलिस के लिए जो कानून और प्रक्रियाएं दीं, वे समय की जरूरत के अनुसार बदलती थीं और तेजी से अद्यतित होती थीं। राजनीतिक दलों द्वारा मामलों का राजनीतिकरण न किए जाने से न्याय त्वरित होता है। ब्रिटेन में हाल ही में हुए दंगों में, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, कुछ दंगइयों को अपराध किए जाने के कुछ ही दिनों के अंदर 20 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है! क्या आप भारत में ऐसा होने की कल्पना

कर सकते हैं? एक अन्य समस्या देश में पुलिस बल की दयनीय स्थिति है। गंभीर अपराध वाले मामलों की तपतीश करने में पुलिस को कई प्रकार के संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। तिस पर संख्या बल कम है। भवन, वाहन, उपकरण आदि से संबंधित ढांचागत कमियों के अलावा साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए लगभग पांच लाख रिक्तियां हैं, सूची अंतहीन है। पुराने ज़माने के कानून और प्रक्रियाएं न्याय प्रदान करने में एक अन्य बाधा है। हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों में भी कई खामियां हैं। दुखद यह है कि इन कानूनों को बनाते वक्त पुलिस अधिकारियों, वकीलों और न्यायाधीशों से सलाह नहीं ली गई है, जबकि आपराधिक मामलों को रोजाना वही देखते हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, केंद्रीय पुलिस बलों को तरजीह देकर राज्य पुलिस बलों की उपेक्षा की गई है, इसके जिम्मेवार कुछ हद तक राज्य सरकारें भी हैं, क्योंकि पुलिस विभाग सूबा सरकार का विषय है। हर कोई, जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश व्यवस्था की तर्ज पर न्यायिक सुधार, यानी त्वरित न्याय की बात कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। न्यायिक अदालतों में लगभग पांच करोड़ मामले लंबित पड़े होने और यह संख्या दिन-ब-दिन बढ़ते जाने से आम नागरिक के लिए कोई उम्मीद नहीं रह गई। इस बाबत कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए, भारत में आम आदमी के लिए न्याय तब तक मिलना मुश्किल है जब तक कि आवश्यक कार्रवाई पर्याप्त तेजी से नहीं की जाती। हमारे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, निकट भविष्य में यह होने की संभावना नहीं है।



प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार एवं हत्या ने न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि समूचे देश में रोष एवं उद्वेलन पैदा किया। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल और पुलिस पर इस घनघन अपराध की जांच में तेजी न लाने का आरोप लगा है। केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार और राज्य सरकार एक-दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं। आरोप-प्रत्यारोपों का राजनीतिक खेल चला हुआ है, जिसमें पुलिस फुटबॉल की तरह बनी हुई है। अब जबकि जनता के भारी दबाव के बाद, जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, तो सूबा सरकार पड़ताल कुछ ही दिनों में पूरी करने की मांग करने लगी है। खुद को राजनीतिक नुकसान से बचाने के लिए, इसके सदस्य आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए। कोलकाता बलात्कार-हत्या

और एक कार्य बल का गठन किया है जो अस्पतालों में सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद सुधार के उपाय बताएगा, और कुछ अन्य सुझाव अपनी तरफ से भी दिए हैं। कोलकाता में कुछ दिन पहले एक और समस्या उत्पन्न हुई, जब शहर के विभिन्न इलाकों में कानून-व्यवस्था की नाजुक स्थिति को संभालने के लिए अधिकांश पुलिस बल की तैनाती के कारण साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच टूर्नामेंट कप फुटबॉल मैच रद्द करना पड़ा। इससे भड़के युवाओं की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लाठीचार्ज किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर, महाराष्ट्र के बदलापुर में दो स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना ने देशभर में व्याप्त आक्रोश को और बढ़ा दिया। हमारे देश में भयावह

क्योंकि मूल बीमारी का इलाज कोई नहीं करना चाहता, केवल लक्षणों का उपचार करने में लगे रहते हैं। व्याधि यह है कि सूबों में पुलिस सत्तारूढ़ दल की निजी सेना बनकर रह गई है क्योंकि पुलिस अधिनियम, 1861 के अंतर्गत वह कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है दृष्टि इसका मतलब है सत्तारूढ़ दल के नेताओं के आदेश से बंधना। कहने की जरूरत नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल पुलिस पर इस किस्म के नियंत्रण से बहुत खुश हैं। यह बात भारत के सभी सूबों और पार्टियों के लिए सच है। इसीलिए आम नागरिक के लिए कोई न्याय नहीं है, क्योंकि पुलिस ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करती है, खासकर जब मामला हाई-प्रोफाइल अपराध का हो। कार्रवाई भी सत्तारूढ़ दल के हितों को ध्यान में रखकर की जाती है। बेशक,

महिला रेलयात्री रहे सजग अधिकारों के लिए

प्रभाकांत कश्यप

पेपर रखने होते हैं, जिन्हें संबंधित



भारत में रेलगाड़ी से सफर करते हुए महिलाओं को कई तरह के विशेषाधिकार हासिल हैं मसलन गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को रेलगाड़ी में निचली बर्थ पाने का विशेषाधिकार है। इसी तरह लोकल ट्रेन में विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बों में भी गर्भवती महिला सफर कर सकती है। आरक्षण फॉर्म में गर्भवती महिला यात्रियों के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है। लेकिन सफर के दौरान एहतियातन उन्हें अपने साथ मेडिकल

अधिकारियों के मांगे जाने पर दिखाने होते हैं। याद रहे ऑनलाइन बुकिंग पर यह सुविधा नहीं मिलती, इसके लिए रिजर्वेशन काउंटर पर गर्भवती होने के मेडिकल पेपर दिखाने पर ही यह सुविधा मिलती है।

टिकट न होने पर भी निर्बाध यात्रा भारतीय रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 139 के अनुसार, यदि कोई महिला बिना पुरुष यात्री के अकेले यात्रा कर रही है और उसके साथ कोई छोटा

बच्चा भी है तो बिना टिकट होने के बाद भी उसे ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई) ट्रेन से उतार नहीं सकता। महिला ज़ुर्माना भरकर अपनी यात्रा जारी रख सकती है। अगर उसके पास ज़ुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं तो भी वह यात्रा का हक रखती है। किसी महिला को ट्रेन से दिन के समय किसी स्टेशन में तभी उतारा जा सकता है जब टीटीई के साथ महिला कांस्टेबल भी हो और वजह टिकट न होने से ज्यादा गंभीर हो।

महिला डिब्बे में सुरक्षा भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार, कोई सैन्य कर्मी भी महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश नहीं कर सकता,उसे सामान्य डिब्बे में यात्रा करनी होगी। महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्री पर कानूनी मुकदमा चलाने का प्रावधान है। रेलवे अधिनियम की धारा 162 के अनुसार, केवल एक संतान जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, को ही किसी महिला के साथ आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति होती है।

सीटों का रिजर्व कोटा भी भारतीय रेलगाड़ियों के स्लीपर क्लास में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर (थर्ड एसी) में चार से पांच और

वातानुकूलित 2 टियर (सेकेंड एसी) में तीन से चार बर्थ विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। गर्भावस्था कोटे में यह सुविधा पाने के लिए महिला के पास डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित गर्भावस्था प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चलती है, तो रेलवे की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को विशेष प्रतीक्षालय प्रदान करेगा,जहां केवल महिलाओं को ही जाने की इजाजत होगी।

सीट बदलवाने का अधिकार भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 139 में कहा गया है कि ट्रेन में अकेली सफर कर रही कोई महिला अगर अपनी सीट को लेकर सहज न हो, तो सफर के दौरान वह टीटीई से बात करके अपनी सीट को बदलवा सकती है। रेलगाड़ी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 182 हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें महिलाएं सुरक्षा संबंधी शिकायतें कर सकती हैं। जबकि रिजर्व कोच में अकेले सफर कर रही महिला की सुरक्षा के लिए कोच में महिला सुरक्षाकर्मी तैनात होती हैं।

स्लीपर क्लास के टिकट पर एसी

में सफर!

रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई अकेली महिला स्लीपर क्लास के टिकट पर एसी क्लास में सफर रही है, तो उसे स्लीपर क्लास में जाने के लिए बोला जा सकता है, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रेलवे बोर्ड के मुताबिक आरक्षित कोच की प्रतीक्षा सूची में भी अगर महिला का नाम नहीं है तो भी उसे ट्रेन से निकाला नहीं जा सकता है। हालांकि, रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर किसी महिला से भी ज़ुर्माना वसूलने और उसे जेल भेजने का प्रावधान है।

फ्री बेबी सीट की सुविधा उत्तर रेलवे ने हाल ही में कुछ रेलगाड़ियों में फ्री बेबी सीट की सुविधा शुरू की है। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली लखनऊ मेल में 2 सीटों के साथ यह सुविधा शुरू की गयी है। यह सुविधा छोटे शिशु के साथ यात्रा करने वाली नई मांओं की ट्रेन यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए किया गया है। अभी रेलवे तय नहीं कर पायी कि इस सुविधा के लिए अतिरिक्त पैसे लिए जायें या नहीं।

पश्चिमी देशों की चमक-दमक का स्याह सच



भारत डोगरा आज सबसे धनी, विशेषकर पश्चिमी देशों के प्रति युवाओं में जबरदस्त आकर्षण है। अनेक युवाओं को लगता है कि किसी भी तरह यदि वहां पहुंच जाएं तो जिंदगी संवर जाएगी। यहां

तक कि कभी-कभी वे और उनके परिवार इसके लिए जमीन-जायदाद तक बेचने को तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अवैध रास्तों से और गैर-कानूनी तौर-तरीकों के साथ तरह-तरह के जोखिम उठाते हैं। उनकी इस आकांक्षा को निरंतर हवा देने के लिए एजेंटों और दलालों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई है, जो करोड़ों कमा रही है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि अति धनी, विशेषकर पश्चिमी देशों के विषय में संतुलित जानकारी प्राप्त की जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका (संक्षेप में अमेरिका), कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है और वहां शहरों की चकाचौंध भी बहुत अधिक है। पर इस चकाचौंध का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे जानना चाहिए। सबसे धनी देश अमेरिका की ही बात करें तो वहां के नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। राष्ट्रीय बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य खर्च पर जाता है। एक वर्ष में 880 अरब डॉलर सैन्य खर्च का सरकारी आंकड़ा है, जबकि इससे कई सैन्य खर्च छूट जाते हैं। अरबन इंस्टीट्यूट के अनुसार, 40 प्रतिशत लोगों के लिए किसी न किसी जरूरत के खर्च को जुटाने में कठिनाई है। किराए पर रहने वाले अधिकांश परिवारों के लिए भी कठिनाई है। लगभग साढ़े छह लाख बेघर लोग हैं। एक वर्ष में 37 लाख लोगों को किराए के घर से जबरन हटाया जाता है। अमेरिका में 50 प्रतिशत विवाहों का अंत तलाक से होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार (यूथ रिस्क

बिहेवियर सर्वे) के अनुसार हाई स्कूल के 42 प्रतिशत छात्र प्रायः दुखी और निराश स्थिति में पाए गए, जबकि एक वर्ष में इनमें से 10 प्रतिशत ने आत्महत्या का प्रयास किया। यदि केवल छात्राओं के आंकड़े देखें तो 57 प्रतिशत दुखी और निराश पाई गई, जबकि 13 प्रतिशत ने एक वर्ष में आत्महत्या का प्रयास किया। 18 प्रतिशत छात्राओं ने यह भी कहा कि उनसे यौन हिंसा या जबरदस्ती का कोई न कोई प्रयास एक वर्ष में किया गया। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टरों के संगठन बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आपात स्थिति घोषित करने के बारे में कह चुके हैं। यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे के जो चौकाने वाले आंकड़े ऊपर दिए गए हैं, वे हर कुछ वर्ष बाद के सर्वेक्षण के बाद एकत्र किए जाते हैं और पिछले लगभग एक दशक से बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि हर सर्वेक्षण के वक्त स्थिति सुधारने के प्रयास करने के बारे में कहा जाता है। चाहे घरेलू हिंसा को देखें या यौन अपराधों को या अन्य तरह की हिंसा को, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़े डराने वाले हैं। यदि जनसंख्या में कैदियों के प्रतिशत को देखें तो विश्व के प्रमुख देशों में यहां का प्रतिशत सबसे अधिक है। सामाजिक स्तर पर भेदभाव को देखें तो अश्वेतों और प्रवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ता है। कम मजदूरी के कठिन श्रम में इनका प्रतिशत अधिक है। श्रम-शक्ति के सबसे निचले हिस्से में शोषण अधिक है और दिन-भर की मेहनत के बाद भी गुजर-बसर कठिन होती है। बारबारा एहरनरिच नामक विख्यात महिला पत्रकार ने इस स्थिति को राष्ट्रीय स्तर

पर दर्शाने के लिए स्वयं कम मजदूरी वाले तीन रोजगार कुछ सप्ताहों के लिए किए और अपने अनुभवों के आधार पर 'निकेल एंड डाइम्ड' नामक पुस्तक लिखी जिससे पता चलता है कि निचले स्तर जैसे सफाईकर्म या वेंटर के स्तर पर किसी महिला मजदूर को कितनी कठिन जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अतः बेहतर होगा कि किसी बाहरी चकाचौंध के चक्कर में रहने के स्थान पर हमारे युवा धनी पश्चिमी देशों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करें। कहीं ऐसा न हो कि वहां जाकर नीचे की श्रेणी में उन्हें अन्याय सहना पड़े। यदि उनके सपने वहां भी पूरे न हों, तो फिर जमीन-जायदाद बेचकर या विभिन्न अन्य कठिनाइयों सहकर वहां जाने से क्या लाभ? इससे कहीं अच्छा होगा कि बहुत चमक-दमक या विलासिता के जीवन के मोह को छोड़ दिया जाए और अपनी मेहनत से अपनी रुचि और क्षमता के अनुकूल उचित आजीविका अपने देश में ही अपनाई जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेश में जाने में कोई बुराई है, वहां अवश्य जाएं पर यदि बेहतर की कोई निश्चित राह आपको नजर आए और इसके लिए जमीन-जायदाद बेचने जैसी गलती न करनी पड़े। ऊंची आय की या सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में ही बहुत सी उम्र गुजार देना भी उचित नहीं है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि कई तरह के ऐसे सार्थक कार्य हो सकते हैं जो टिकाऊ हैं, हमारी रुचि और क्षमता के अनुकूल हैं और बेहतर समाज और देश बनाने में भी सहायक हैं। इस तरह के कार्यों में स्व-रोजगार को आगे बढ़ाना भी समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है।

फेस सीरम स्किन पर लाये कुदरती चमक



नीलोफर

फेस सीरम विशेष रूप से चेहरे की केयर करने वाले ब्यूटी उत्पाद होते हैं, ये चेहरे की त्वचा की गहरी परतों में जाकर उसे हाईड्रेट करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं और कुदरती चमक बढ़ाते हैं। क्योंकि ये अत्यधिक केंद्रित फार्मूले के साथ बनाये जाते हैं, जो त्वचा को बिल्कुल जीवंत कर देते हैं। फेस सीरम में बहुत ही पॉवरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये त्वचा में बहुत गहरे तक जाकर उसकी टूट-फूट दुरुस्त करते हैं। फेस सीरम कई तरह के होते हैं। इनका उपयोग तब बेहतर होता है, जब उम्र बढ़ने लगे और चेहरे में बढ़ती उम्र के लक्षण दिखने लगें। क्योंकि इस उम्र में त्वचा का कोलेजन धीमा हो जाता है, ऐसे में त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। इससे छुटकारा दिलाने में फेस सीरम काफी मददगार होते हैं। जानिये कौन सा फेस सीरम हमारी त्वचा को किस तरह से फायदा पहुंचाता है।

एंटी एजिंग नाइट सीरम

जब उम्र बढ़ने लगे, चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगें तो इस सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सीरम चेहरे की गंदगी को पूरी तरह निकाल देते हैं। त्वचा को गहरे तक जाकर हाईड्रेट करते हैं, जिससे उसका मुरझायापन

दूर हो जाता है या कम होता है। हालांकि दुनिया की कोई चीज कभी उम्र को रोक नहीं सकती, लेकिन यह बढ़ती उम्र की रफ्तार धीमी कर देता है और चेहरे के दाग-धब्बों को या तो पूरी तरह खत्म कर देता है या काफी हल्का कर देता है। इससे झुर्रियां नजर नहीं आती। वास्तव में ये कोलेजन उत्पादन में मदद करते हैं। इस सीरम का एक घटक रेटिनोल होता है। यह कोलेजन के टूटने को रोकता है या धीमा करता है, जिससे त्वचा टाइट रहती है।

विटामिन सी फेस सीरम

विटामिन सी साफ, सुंदर और मुलायम त्वचा पाने में बहुत मददगार होती है। विटामिन सी फेस सीरम चेहरे की त्वचा को आकर्षक बनाता है। यह अकेले ऐसा नहीं करती बल्कि इस सीरम में मौजूद विच हेजल हाईल्यूरोनिक एसिड तथा फेरुलिक एसिड के साथ त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन को बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा में नमी बढ़ती है, महीन झुर्रियां कम होती हैं या गायब हो जाती हैं। चेहरा रंगत से भरपूर नजर आता है।

उबटन फेस सीरम

यह एक प्राकृतिक फेस सीरम है, इससे चेहरे की त्वचा चमकदार और साफ होती है। यह उत्पाद हाईल्यूरोनिक एसिड तेल और खनिजों से समृद्ध होता

है। यह सीरम त्वचा की झुर्रियां दूर करता है और बढ़ती उम्र की रफ्तार को धीमा करता है। इसे दो बार लगाना चाहिए, एक बार त्वचा साफ करने के लिए और दूसरी बार इसे साफ त्वचा में लगाना चाहिए, तब इसके फायदे और स्पष्ट दिखते हैं।

ग्रीन टी फेस सीरम

यह पीएच संतुलित हल्का और सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त सीरम है। इसमें प्राकृतिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। यह सिलिकॉन और पैराबेन मुक्त होता है। स्वस्थ त्वचा के लिए इसे दिन में दो बार लगाना चाहिए। इससे आपकी त्वचा एक बार फिर से खिल उठती है।

गुलाब फेस सीरम

इस सीरम में गुलाब का तेल, चुकंदर का अर्क और विटामिन ई जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं। ये पूरी तरह शाकाहारी सीरम है। यह चेहरे की त्वचा की मॉश्चराइजिंग, ब्राइटनिंग करता है और फ्री रेडिकल्स से मुक्ति दिलाता है। यह त्वचा को फूलों की माफिक सुंदर और खुशबूदार बनाता है। निश्चित रूप से ढीली और मुरझाती त्वचा को फेस सीरम कसावट पूर्ण बनाते हैं। साफ-सुथरी और जितना संभव है, दाग-धब्बों से मुक्त करते हैं। इनसे चेहरे की ग्लो बढ़ती है। खासकर विटामिन सी सीरम से चेहरे में कसाव आता है।

Kolkata doctor rape and murder protest LIVE: Police stops Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury from visiting R.G. Kar Hospital

Ahead of the upcoming special session of the West Bengal Legislative Assembly, the Trinamool Congress has stepped up the campaign demanding capital punishment for those convicted of rape. The Assembly Session has been convened to pass legislation along similar lines.

The Calcutta High Court directed the the release of Paschim Banga Chhatra Samaj leader Sayan Lahiri and added that no coercive action can be taken against him. The Federation of All India Medical Association (FAIMA) will hold a peaceful protest at Jantar Mantar in Delhi on Saturday, August 31, 2024 over the rape and murder of a trainee doctor at the R.G. Kar College and Hospital in Kolkata.

According to the statement issued by FAIMA, the protest aims to demand justice for the victim and press the government to expedite the enactment of the long-pending Central

Venice 2024: Angelina Jolie's Maria Callas biopic receives 10-minute standing ovation at festival



The biopic, which is in competition at the festival, captures the final days of opera singer Maria Callas' life, exploring the intense passion that defined her career and ultimately consumed her

Director Pablo Larrain and Angelina Jolie pose for photographers upon arrival for the premiere of the film 'Maria' during the 81st edition of the Venice Film Festival

Director Pablo Larrain and Angelina Jolie pose for photographers upon arrival for the premiere of the film 'Maria' during the 81st edition of the Venice Film Festival | Photo Credit: Vianney Le Caer

Pablo Larraín's Maria, starring Angelina Jolie as the legendary opera singer Maria Callas, received a 10-minute standing ovation at its world premiere at the Venice Film Festival on Thursday night. The biopic, which is in competition at the festival, captures the final days of Callas' life, exploring the intense passion that defined her career and ultimately consumed her.

The screening at the Sala Grande left the audience deeply moved, with many chanting Jolie's name. Jolie, who has been nominated for two Oscars, became emotional as she acknowledged the crowd, shedding a tear as she descended from the gallery to greet the audience. The film's cast, including Pierfrancesco Favino and Alba Rohrwacher, joined Larraín and Jolie at the premiere.



Healthcare Protection Act, which seeks to ensure the safety of healthcare professionals across the country.

Also Read | WCD Minister urges West Bengal CM to strengthen Fast Track Special Courts for rape, POCSO cases

Meanwhile, the National

T.N. CM Stalin signs MoU with Google for AI labs, meets officials of Apple and Microsoft

In the presence of Chief Minister M.K. Stalin, the Tamil Nadu government signs an MoU with Google to set up AI laboratories in the State

In the presence of Chief Minister M.K. Stalin, the Tamil

Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Kolkata Police Commissioner over the alleged use of excessive and brutal force on August 27 on protesters, who were demonstrating to demand justice for the victim in the RG Kar Medical College rape-murder case.

Nadu government signs an MoU with Google to set up AI laboratories in the State | Photo Credit: Special Arrangement

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, who is touring the United States to attract investments, signed a memorandum of understanding (MoU) with Google to set up AI laboratories in the State. He also met senior officials of Apple and Microsoft and invited them to invest in Tamil Nadu.

"An awe-inspiring visit to the offices of Apple, Google and Microsoft. Discussed various opportunities and exciting partnerships. Determined to strengthen these partnerships and make Tamil Nadu one of the foremost growth engines of Asia," Mr. Stalin said in a social media post.

Why are cyclones in the Arabian Sea not so common?

Satellite image taken between 12:15 to 12:45 IST on August 30, 2024, shows the location of a deep depression over the Kutch coast and adjoining areas of Pakistan and the northeast Arabian sea.

Satellite image taken between 12:15 to 12:45 IST on August 30, 2024, shows the location of a deep depression over the Kutch coast and adjoining areas of Pakistan and the northeast Arabian sea. | Photo Credit: PTI

The North Indian Ocean supplies a large part of the moisture required to generate the 200 lakh crore or so buckets of water during the summer monsoon. That implies a lot of evaporation from the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which requires these seas to be warm enough to allow evaporation. Warm tropical oceans also tend to be hotbeds of cyclones. And yet, the North Indian Ocean is the least active region of the world's oceans vis-à-vis the number of cyclones. The combination of some factors that favour cyclogenesis and some that suppress it make this area unusual in terms of cyclone seasons, numbers, and the response of the ocean and the cyclones to global warming.

Hateful, baleful: On the Assam Chief Minister and communally sensitive remarks

Hate speech, especially by elected authorities and targeting a specific community, has been repeatedly flagged as a possible trigger for ethnic conflagrations and atrocities that could have catastrophic consequences. Politicians in India are well aware of this but this does not deter the most cynical among them from using hate speech to further a polarising agenda. A case in point is the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma. The BJP leader continues to revel in making communally sensitive remarks, targeting the State's minority communities. On Tuesday, he explicitly said that he would take sides against "Miya Muslims" — a discriminatory euphemism for the minority Bengali Muslim community — and would not let them "go to Upper Assam". These remarks were in the context of a debate on the law and order situation after a gangrape of a minor in Dhing. During the 2024 general election, Mr. Sarma, in speech after speech, had used rabidly communal language to target Muslims, with nary a response from the Election Commission of India. He even said, "Islamophobia is real for many of us [Hindus]".

By making these statements repeatedly, Mr. Sarma is going against the oath he took as the Chief Minister — that he will bear true faith and allegiance to India's secular Constitution. He should be condemned

for explicitly saying that he will side against a particular community. Second, by amplifying demands by groups that have threatened an entire community to leave "Upper Assam" and suggesting that the minority community does not have the right to free movement, he is furthering hate in a State which has been affected by ethnic violence. From violent anti-immigrant agitations to militancy and a flawed process of identifying "foreigners" that has brought misery to the poor, Assam has been through crises; some of those issues continue to fester. Instead of finding ways of reconciliation, all-round harmony and peace, he uses the cynical ploy of fostering division in order to reap the benefits out of the politics of hate. As actions in nearby Myanmar and the plight of the Rohingya show, repeated use of hate speech to characterise a minority community and the amplification of communalism have disastrous consequences. The Union government and the BJP leadership have shown no inclination to rein in the errant Chief Minister. Unlike party leaders who have been reprimanded for utterances targeting sections such as farmers, Mr. Sarma uses hate speech against Muslims. But if the government is serious about improving the lot of the Assamese people — the State has among the poorest HDI indicators in the country — it has to put an end to hate speech as a communally charged environment militates against all-round development.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
शक्ति शंकर द्वारा फाईन
आफसेट प्रिंटर्स मद्रास
हुसेनिया बिल्डिंग बक्शीपुर,
जनपद-गोरखपुर से मुद्रित
कराकर, मुहल्ला-द्वितीय तल
पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही
मार्केट, गोलघर,
जनपद-गोरखपुर से
प्रकाशित।
प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र
गोरखपुर न्यायालय होगा।